उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग गहरे संकट में

चीनी अपने उत्पादकों और किसानों के लिए ही कड़वी हो गई है...

30,000 करोड़ का चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के समान है।

यह उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सालाना 6150 करोड़ रुपए का योगदान देता है।

- चीनी पर प्रवेश कर के रूप में 185 करोड़ रुपए।
- गन्ना खरीद कर और गन्ने पर सोसायटी कमीशन के मद में 650 करोड़ रुपए।
- प्रशासनिक कर और शीरे की बिक्री पर वैट के मद में 96 करोड़ रुपए।
- शीरे से निर्मित पेय एल्कोहल पर वैट के रूप में 5200 करोड़ रुपए।

उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग से जुड़े दुःखद तथ्य।

- यह उद्योग देश में गन्ना मूल्यों का सर्वाधिक भुगतान करता है।
- गत तीन वर्षों मात्र में ही गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य 70 प्रतिशत बढ़ चुका है।
- हालाँकि, इन तीन वर्षों में चीनी के मूल्यों में सिर्फ 6 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है।
- आज अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में चीनी के उत्पादन की लागत 14–16 प्रतिशत अधिक है।
- 2012–13 में चीनी की बिक्री से प्राप्त 94 प्रतिशत धनराशि गन्ना मूल्यों के भुगतान मात्र में खर्च हो गई है। अन्य भुगतान करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है।
- हर एक किलो चीनी पर मिलों को 4 रुपए की हानि हो रही है।

उत्तर प्रदेश के चीनी सेक्टर में आर्थिक बदहाली का दौर, किसानों को भी हानि हो रही है

- विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग को निरंतर हानि हुई है।
- 2012–13 के सत्र मात्र में ही 3000 करोड़ रुपए की हानि हो गई है। (पिछले दो सालों में 4000 करोड़ रुपये)।
- आधी मिलों को इतनी भी आय नहीं हो रही कि वे अपने बैंक कर्जों के ब्याज का भुगतान कर सकें।
- 2012–13 के दौरान गन्ना मूल्यों में अत्यधिक अनुचित बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप ही किसानों के बकाये ऐतिहासिक स्तर तक जा पहुँचे हैं।
- बैंक उत्तर प्रदेश के गन्ना उद्योग को अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल के लिए ऋण देने को तैयार नहीं हैं।
- अनेक चीनी मिलें 2013–14 के लिए कामकाज शुरु करने की स्थिति में नहीं हैं।
- चीनी मिलों की तरफ से उत्तर प्रदेश बिजली निगम लिमिटेड को की गई बिजली सप्लाई के 500 करोड़ रुपए के बकायों का भुगतान आज भी लंबित है।

upsma

उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन